दैनिक भारत कि
तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com
Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-२ ला | अंक-११० वा | बुधवार १३ मे २०२६ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

शिक्षण अधिकारियों की मनमानी पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार; दोबारा गलती की तो खैर नहीं, अल्पसंख्यक स्कूलों को टीईटीसे बड़ी राहत

छत्रपति संभाजीनगर :

मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य नहीं है। बार-बार स्पष्ट आदेश दिए जाने के बावजूद टीईटी के नाम पर शिक्षकों के नियुक्ति प्रस्ताव खारिज करने वाले शिक्षा अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर न्यायालय ने तीव्र नाराजगी जताई है। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा हुई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

सय्यद अबू ज़ैद सय्यद रफीक, गायकवाड सायली व्यंकटेश और साईनाथ गणपत बनसोडे इन शिक्षकों की शिक्षण सेवक पद पर नियुक्ति को शिक्षा अधिकारियों ने मान्यता देने से इनकार कर दिया था। शिक्षा विभाग का कहना था कि इन शिक्षकों ने टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। इसके खिलाफ संबंधित शिक्षकों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। ▶▶पान ४ पे

बीड़ जिले के विकास का अजित दादा पवार का सपना सुनेत्रा वहिनी के माध्यम से पूरा होगा।

गेवराई के विधायक विजयसिंह पंडित का संकल्प

बीड़ (काजी अमान): महाराष्ट्र के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और बीड़ जिले के संरक्षक मंत्री स्वर्गीय अजितदादा पवार के माध्यम से बीड़वासियों ने विकास का आशापूर्ण चित्र देखा था। स्व. अजितदादा ने अनेक विकास कार्यों को मंजूरी देते हुए नए विकास का विजन जनता के सामने रखा था। उनकी कल्पना के विकास कार्यों को उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा वहिनी अजित पवार के माध्यम से पूरा कराने की जिम्मेदारी मेरी है। राजनीति से ज्यादा विकास कार्य महत्वपूर्ण हैं, इसलिए स्व. अजितदादा की संकल्पना वाले विकास कार्यों को पूर्ण करने के लिए पूरे प्रयास करूंगा। यह घोषणा गेवराई के आमदार विजयसिंह पंडित ने की।

माजी आमदार अमरसिंह पंडित की प्रमुख उपस्थिति में जिलाधिकारी विवेक जॉन्सन की अध्यक्षता में गेवराई और बीड़ के विकास कार्यों की समीक्षा के बाद वे बोल रहे थे। आ. विजयसिंह पंडित द्वारा विकास कार्यों की समीक्षा आ. विजयसिंह पंडित ने सोमवार, दिनांक ११ मई २०२६ को जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी विवेक जॉन्सन की उपस्थिति में गेवराई विधानसभा क्षेत्र तथा बीड़ शहर के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।

इस दौरान निम्नलिखित विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई:

रेशम पार्क, गेवराई एमआईडीसी आपदा न्यूनीकरण संबंधी कार्य बीड़ एमआईडीसी बीड़ शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य (जिसमें देरी हो रही है) बीड़

शहर में अमृत जल आपूर्ति योजना अधर में लटकी भूगर्भीय नाला (सीवर) योजना विज्ञान केंद्र व तारागृह का निर्माण यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह का नवीनीकरण खेल संकुल का विकास खाका स्व. अजितदादा पवार का स्मारक मौजे कपिलधारवाड़ी गांव का पुनर्वास इस बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मचारी तथा बीड़ नगर परिषद के पदाधिकारी उपस्थित थे।

नगराध्यक्षा प्रेमलता पारवे, उपनगराध्यक्ष विनोद मुलूक, नगराध्यक्ष प्रतिनिधि शेख मुजीब, सभापति शेख निजाम, गटनेता फारूक पटेल, नगर सेवक अशफाक इनामदार सहित अन्य मान्यवरों ने चर्चा में भाग लिया।

मुख्य चर्चा के मुद्दे:

माजी आमदार अमरसिंह पंडित के मार्गदर्शन में आ. विजयसिंह पंडित ने गेवराई विधानसभा क्षेत्र और बीड़ शहर के सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। गेवराई में प्रस्तावित रेशम पार्क के आराखड़े का प्रस्तुतीकरण किया गया। स्व. अजितदादा द्वारा बताई गई हर बात को इस आराखड़े में शामिल करने के निर्देश आ. पंडित ने दिए। मौजे आहेरवाहेगांव में गेवराई तालुका औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि उद्योग विभाग को हस्तांतरित हो चुकी है। दो माह के अंदर भूखंड आवंटन प्रक्रिया पूरी कर आंतरिक सड़कें, पानी, बिजली आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई।

सितंबर २०२५ में हुई अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कें, पुल, बांध और नदी किनारे के गांवों की खेती आदि के संबंध में जिला आपदा प्रबंधन समिति द्वारा तैयार प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सिंदफणा नदी पर अंकुटा व खुंड्रस में सुरक्षा दीवार तथा गोदावरी नदी तट पर खामगांव और राजापुर में घाट निर्माण के प्रस्ताव शासन को मंजूरी के लिए भेजने का निर्णय लिया गया।

अमृत योजना और भूगर्भीय नाला योजना:

बीड़ शहर के लिए वर्ष २०१७ में मंजूर अमृत जल आपूर्ति योजना अभी तक नगर परिषद को हस्तांतरित नहीं हुई है। जलकुंभ बंद होने, वितरण व्यवस्था अधूरी होने सहित अन्य तकनीकी मुद्दों पर चर्चा हुई।

वर्ष २०१८ में १६५ करोड़ रुपये की भूगर्भीय नाला योजना ▶▶पान ४ पे

लोकों को ब्रह्मज्ञान सिखाने वाले खुद कोरड़े पाषाण की हालत: मोदी और भाजपा की यही स्थिति है-नाना पटोले का तंज

मुंबई: जमीर काजी

राज्य में सत्ताधारी दल के मंत्री और विधायक सुरक्षा के नाम पर बड़े-बड़े काफिले लेकर घूम रहे हैं। सरकारी व्यवस्था और जनता के पैसों की भारी उड़ाई चल रही है। राज्य के कई मंत्री आज गुवाहाटी गए हैं। दूसरों को ब्रह्मज्ञान सिखाना और खुद ऐशो-आराम की जिंदगी जीना - यही भाजपा की कार्यशैली है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक नाना पटोले ने मंगलवार को इस मुद्दे पर जोरदार हमला बोला।

पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, देश की कई महत्वपूर्ण संस्थाओं और व्यवस्थाओं को बेचने का रास्ता अपनाया गया है। सभी राज्यों पर कब्जा करने की राजनीति चल रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने देश का नक्शा जारी करके बताया कि कितने राज्यों में उसकी सत्ता है। खुद अपनी पीठ थपथपाने का काम भाजपा सरकार कर रही है।

भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और खुद प्रधानमंत्री कैसे व्यवहार कर रहे हैं, इस पर पूरा देश नजर रखे हुए है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मधू दंडवते ने कठिन परिस्थितियों में खुद से किफायत शुरू की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और लालबहादुर शास्त्री ने भी खुद उदाहरण पेश किया था। उन्होंने देश के लिए आदर्श और मार्गदर्शक व्यवस्था बनाई। लेकिन भाजपा सरकार से ऐसी जिम्मेदार भूमिका की किसी को उम्मीद नहीं है।

भाजपा १३ साल से सत्ता में होने के बावजूद देश की जो स्थिति बनी है, उसे छिपाने के लिए अलग-अलग मुद्दे सामने लाए जा रहे हैं। उस समय देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति लाकर देश को आत्मनिर्भर बनाया। भाजपा को इन ऐतिहासिक बातों का भी जिक्र करना चाहिए।

आज देश अमेरिका के दबाव में काम कर रहा है, ऐसी भावना जनता में पैदा हो गई है। भारत ने पहले कभी किसी देश के सामने समर्पण नहीं किया। राहुल गांधी ने कई बार इस मुद्दे पर अपनी भूमिका रखी है। मैंने खुद इस संबंध में पत्र-व्यवहार किया है और वरिष्ठ नेता शरद पवार ने भी ▶▶पान ४ पे

राष्ट्रवादी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से फिर बाहर हुए प्रफुल्ल पटेल और तटकरे, पार्टी में अंदरूनी कलह की चर्चा तेज

सुनेत्रा पवारने बताया तकनीकी गलती

तकनीकी और क्लेरिकल गलती-सुनेत्रा पवार

इस पूरे मामले पर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने 'एक्स' पर पोस्ट कर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि यह तकनीकी और क्लेरिकल (लिपिकीय) गलती है। सोशल मीडिया और मीडिया में वायरल हो रही सूची गलत है और जल्द ही संशोधित सूची जारी की जाएगी।

जमीर काज़ी

मुंबई : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी से कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे के नाम एक बार फिर गायब पाए गए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग को सौंपे गए दस्तावेज़ों में दूसरी बार उनके नाम शामिल न होने से राजनीतिक गलियारों में भारी हलचल मच गई है।

पार्टी प्रमुख और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने इसे तकनीकी त्रुटि बताया है, लेकिन पार्टी के भीतर गुटबाजी के कारण ऐसा होने की चर्चा जोरों पर है।

पार्टी की ओर से २९ अप्रैल को चुनाव आयोग को सौंपे गए पत्र में नई कार्यकारिणी में पार्थ पवार और जय पवार को राष्ट्रीय महासचिव तथा सचिव पद दिए गए हैं, लेकिन प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के नाम सूची में शामिल नहीं किए गए। इससे पहले भी प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाए जाने की चर्चाएं सामने आई थीं। अब दोबारा दोनों नेताओं के नाम हटने से पार्टी के भीतर छिपे संघर्ष की अटकलें तेज हो गई हैं।

राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद पार्टी के संगठनात्मक नियंत्रण को लेकर वरिष्ठ नेताओं - प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे - तथा पार्थ पवार के बीच अंदरूनी संघर्ष चल रहा है।

संगठन में बदलाव के बाद बढ़ी राजनीतिक हलचल

पार्टी सूत्रों के अनुसार, अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार ने पार्टी की कमान संभाली है और संगठन में कई बदलाव किए जा रहे हैं। इन घटनाक्रमों के चलते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) की आंतरिक राजनीति एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है।

महाराष्ट्र के लिए अगले तीन दिन बेहद खतरनाक, हीटवेव का अलर्ट जारी

मुंबई, १२ मई (प्रतिनिधि) : राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान ४० डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। इसी बीच महाराष्ट्र में अगले तीन दिनों तक भीषण गर्मी और लू (हीटवेव) चलने की चेतावनी जारी की गई है। विशेष रूप से मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्र में तापमान अत्यधिक बढ़ने की संभावना जताई गई है। पुणे मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ▶▶पान ४ पे

नीट पेपर लीक प्रकरण में महासंचालक अभिषेक सिंह को गिरफ्तार करो-हर्षवर्धन सपकाळ

माफिया खुलेआम; लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़

मुंबई: जमीर काजी

भाजपा की केंद्र और कई राज्यों में सरकार आने के बाद अपराधियों का सिर उठा है और शिक्षा क्षेत्र में भी माफियाराज का घुसपैठ शुरू हो गया है। नीट (NEET) का पेपर लीक होने के कारण इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा कराने की मजबूरी आ पड़ी है। पेपर लीक करने वाले माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। इस मामले में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NT-) के महासंचालक अभिषेक सिंह को बर्खास्त कर उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए, यह मांग महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने की है।

उन्होंने कहा कि ३ मई को नीट परीक्षा देशभर में हुई थी। पूरे साल मेहनत करके छात्र परीक्षा देते हैं और ऐसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। यह छात्रों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। अब दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। इस फेर परीक्षा से सिर्फ २२.६९ लाख छात्रों को ▶▶पान ४ पे

मोदी पहले अपने दौरे और काफिले रोकें, फिर जनता को उपदेश दें: राज ठाकरे का हमला!

तात्कालिक सर्वपक्षीय बैठक बुलाएं-शरद पवार

मुंबई: जमीर काजी

पेट्रोल, डीजल और खाना पकाने के तेल के उपयोग को कम करने की अपील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद विपक्ष ने तीखी आलोचना शुरू कर दी है।

मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी पहले खुद अपने दौरे और काफिले बंद करें, उसके बाद जनता को उपदेश दें। वहीं, वरिष्ठ नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री से तत्काल सर्वपक्षीय बैठक बुलाने की मांग की है।

ईरान-अमेरिका तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है। इसी पृष्ठभूमि पर रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से किफायत बरतने की अपील की थी, जिसके बाद विभिन्न स्तरों पर उनकी तीखी आलोचना हो रही है।

राज ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस नेता नाना पटोले, हर्षवर्धन सपकाळ, सचिन सावंत आदि ने सोशल मीडिया (एक्स) पर पोस्ट कर सरकार की आलोचना की।

राज ठाकरे का हमला:

राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर जारी एक पत्र में केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों, बढ़ती महंगाई और ईंधन दरों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा:

सोना कम खरीदें, पेट्रोल-डीजल कम इस्तेमाल करें, विदेश दौरे टालें और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं - ऐसा कहने वाले प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी खुद देशभर में सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ रोड शो और जुलूस निकाल रहे हैं। ▶▶पान ४ पे

प्रो. सलीम इंजीनियरने NEET २०२६ में हुई अनियमितताओं की निंदा करते हुए स्वतंत्र जाँच और कड़ी कार्रवाई की माँग की

नई दिल्ली, १२ मई २०२६

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के तहत मरकज़ी तालीमी बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने एनईईटी यूजी २०२६ परीक्षा में अनियमितताओं की कड़ी निंदा की है जिसके कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी। उन्होंने परीक्षा की शुचिता और निष्पक्षता को बनाए रखने में विफल रहने तथा चिकित्सा क्षेत्र में देश की सेवा करने के आकांक्षी लाखों छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने के लिए सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को ज़िम्मेदार ठहराया।

मीडिया को जारी एक बयान में तालीमी बोर्ड के चेयरमैन ने कहा, हम नीट यूजी २०२६ परीक्षा में हुई उन अनियमितताओं की कड़ी निंदा करते हैं जिनके कारण इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। नीट परीक्षा देश की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी प्रवेश परीक्षाओं में से एक है जिसमें हर साल २० लाख से भी ज़्यादा छात्र शामिल होते हैं। एक ऐसे 'गेस पेपर' जिसमें वास्तविक परीक्षा से मेल खाने वाले सवालों की बड़ी संख्या शामिल है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा संचालित प्रक्रिया की निष्पक्षता में एक गंभीर सेंध का संकेत देता है। अनौपचारिक नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए ऐसे बेहद सटीक 'गेस पेपर्स' की बिक्री और बड़े पैमाने पर उनका सर्कुलेशन, संगठित कदाचार की ओर इशारा करता है। इस तरह के पेपर लीक परीक्षा प्रणाली में जनता के भरोसे को कमज़ोर करते हैं, और छात्रों व अभिभावकों के बीच योग्यता तथा समान अवसर को लेकर विश्वास का गंभीर संकट पैदा करते हैं। हम इस विफलता के लिए सरकार और छढ- को सीधे तौर पर ज़िम्मेदार मानते हैं, जिसने लाखों छएएढ उम्मीदवारों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है।

प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने आगे कहा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नीट यूजी २०२६ परीक्षा को रद्द करने और उसे दोबारा आयोजित करने का फ़ैसला, साथ ही सरकार का इस मामले को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन को सौंपने का कदम, परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की गंभीरता की साफ़ तौर पर स्वीकारोक्ति है। हालाँकि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह निर्णय आवश्यक था लेकिन इसने लाखों छात्रों और उनके परिवारों के लिए भारी मानसिक कष्ट और अनिश्चितता पैदा कर दी है। इस उल्लंघन के लिए सीधे तौर पर ज़िम्मेदार लोगों की पहचान की जानी चाहिए और उनके साथ यथासंभव कठोरता से निपटा जाना चाहिए, ताकि यह एक मज़बूत निवारक के रूप में काम कर सके। इसके साथ ही छढ- और शिक्षा मंत्रालय की कमान संभालने वालों को इन असफलताओं की जवाबदेही स्वीकार करते हुए इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और नैतिक ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए।

मरकज़ी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन प्रो. सलीम इंजीनियर ने कहा, तथ्य का पता लगाने और सभी स्तरों पर जवाबदेही तय करने के लिए इस मामले की गहन, स्वतंत्र और समय- बद्ध जांच की तत्काल आवश्यकता है। हम अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वे जाँच प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करें और किसी भी ऐसे व्यक्ति या नेटवर्क के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें जो कदाचार का दोषी पाया जाता है। हम परीक्षा सुरक्षा को सुदृढ़ करने, निगरानी तंत्र को बेहतर बनाने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रणालीगत सुधारों की मांग करते हैं। सरकार को शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्व खडठज अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञों की उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों को तत्काल लागू करना चाहिए; इस समिति ने प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं को लेकर चिंता जताई थी और एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता पर ज़ोर दिया था जो 'सुरक्षित, छेड़छाड़-मुक्त और पारदर्शी' हो। छढ- को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टेस्टिंग प्रक्रिया के पूरे चक्र में मौजूद कमियों को दूर किया जाए, और समिति द्वारा सुझाए गए अनुसार, कदाचार को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं।

नेकनूर-सफेपूर सड़क और पुल निर्माण कार्य को मिली गति, विधायक नमिता मुंदड़ा के प्रयास सफल

केज : नेकनूर से सफेपूर तक दो किलोमीटर लंबी डामरी सड़क और पुल निर्माण का कार्य अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। केज विधानसभा क्षेत्र की विधायक नमिता अक्षय मुंदड़ा के लगातार प्रयासों के कारण लंबे समय से लंबित यह परियोजना अब पटरी पर आ गई है। इस कार्य से स्थानीय नागरिकों, विद्यार्थियों और मरीजों की वर्षों पुरानी परेशानी दूर होने वाली है, जिससे क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

नेकनूर क्षेत्र की इस अत्यंत महत्वपूर्ण सड़क का काम कई दिनों से अधूरा पड़ा था, जिसके कारण ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। नागरिकों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए विधायक नमिता मुंदड़ा ने शासन स्तर पर लगातार इस मुद्दे का गंभीरता से पीछा किया। उनके प्रयासों को सफलता मिली और अब सड़क के डामरीकरण तथा पुल निर्माण कार्य की वास्तविक शुरुआत हो चुकी है।

इस विकास कार्य से श्रीगुरु बंकटस्वामी मठ स्थित दत्त मंदिर और नामदेव मंदिर जैसे प्रमुख श्रद्धास्थलों तक पहुंचने का मार्ग भी सुगम हो जाएगा। इस सड़क का सबसे अधिक लाभ स्कूली विद्यार्थियों, शिक्षक कॉलोनी, मतेखा मोहल्ला और कल्याणकर मळा क्षेत्र के निवासियों को मिलेगा। विशेष रूप से महिला एवं कुटीर अस्पताल जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को इस कार्य से बड़ी राहत मिलेगी तथा यातायात संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए विधायक नमिता मुंदड़ा ने मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis, उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde, उपमुख्यमंत्री ajit Pawar तथा मंत्री Pankaja Munde का विशेष आभार व्यक्त किया है।

नेकनूर क्षेत्र की जनता ने अपने अधिकार की सड़क और पुल निर्माण कार्य शुरू होने पर विधायक नमिता मुंदड़ा की सक्रियता और कार्यशैली की सराहना की है।

माजलगांव के लॉज में देह व्यापार की चर्चा, पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग

माजलगांव । प्रतिनिधि

शहर के बीचों-बीच स्थित एक लॉज में कथित रूप से देह व्यापार चलाए जाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। शहर के प्रमुख और व्यस्त इलाके में चल रहे इस कथित गैरकानूनी गतिविधि की ओर प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा अनदेखी किए जाने का आरोप नागरिकों द्वारा लगाया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि इस धंधे से होने वाली कमाई के बल पर संबंधित लॉज मालिक ने बड़ी आर्थिक संपत्ति खड़ी कर ली है।

शहर में दिन-ब-दिन संदिग्ध गतिविधियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं और कुछ लॉज अनैतिक कारोबार के केंद्र बनते जा रहे हैं, ऐसी चर्चा नागरिकों के बीच हो रही है। देर रात तक संदिग्ध लोगों की आवाजाही, बाहर से आने वाले वाहनों की भीड़ तथा कुछ एजेंटों के माध्यम से ग्राहकों को महिलाओं की आपूर्ति किए जाने की बातें इलाके में सुनने को मिल रही हैं।

स्थानीय नागरिकों के अनुसार, कुछ निजी एजेंट ग्राहकों से संपर्क कर महिलाओं को लॉज तक पहुंचाने का काम करते हैं और यह पूरा कारोबार सुनियोजित तरीके से चलाया जाता है। विशेष बात यह है कि एड्स जैसे गंभीर रोगों का खतरा बढ़ने के बावजूद इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगती दिखाई नहीं दे रही है।

समाज में जागरूकता बढ़ने के बावजूद कुछ लोग अब भी ऐसे स्थानों पर जाते दिखाई दे रहे हैं। इससे शहर का सामाजिक वातावरण प्रभावित हो रहा है और युवाओं पर इसका नकारात्मक असर पड़ने की चिंता अभिभावकों द्वारा व्यक्त की जा रही है।

नागरिकों ने मांग की है कि पुलिस प्रशासन इस मामले की तत्काल जांच कर सच्चाई जनता के सामने लाए।

पान १ वरून

बीड़ जिले के विकास का अजित...

आधी-अधूरी छोड़कर ठेकेदारों ने करोड़ों रुपये की राशि निकाल ली। दोनों योजनाओं में ठेकेदारों द्वारा बिना काम किए सैकड़ों करोड़ रुपये निकालने की बात सामने आई।

मंत्रालय स्तर पर कार्यवाही कर पेयजल और मलनिस्सारण के संबंध में नई कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग का मुद्दा:

बीड़ शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ३६१-ऋका काम देरी से चल रहा है, जिससे नागरिकों में नाराजगी है। पावस (मानसून) से पहले राजमार्ग और नालों के काम पूरे करने के निर्देश दिए गए। राजमार्ग के इंजीनियर की बाधक भूमिका के कारण शहर में पानी का निकास नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी विवेक जॉन्सन ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि समय पर काम न करने वाले ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नगर पालिका और राजमार्ग अभियंताओं को समन्वय से काम करने के निर्देश दिए।

अन्य महत्वपूर्ण कार्य:

यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह का नवीनीकरण, २५ करोड़ रुपये के जिला खेल संकुल विकास आराखड़े, विज्ञान केंद्र व तारागृह निर्माण, स्व. अजितदादा पवार स्मारक निर्माण आदि कार्यों की समीक्षा की गई। इन सभी कार्यों को शीघ्र ही औपचारिक रूप से शुरू करने का निर्णय लिया गया। जिला खेल संकुल को पहले छत्रपती शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाता है, लेकिन शासन दस्तावेज में इसका उल्लेख नहीं है। शीघ्र उच्चस्तरीय बैठक लेकर तकनीकी कार्यवाही पूरी करने का निर्णय लिया गया।

आ. विजयसिंह पंडित का वक्तव्य:

जिलाधिकारी कार्यालय में हुई विकास कार्यों की समीक्षा की जानकारी देते हुए आ. विजयसिंह पंडित ने कहा कि स्व. अजितदादा पवार साहेब की संकल्पना वाले विकास कार्यों को उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा वहिनी पवार के माध्यम से पूर्ण करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

उपस्थित प्रमुख अधिकारी:

उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव उपजिल्हाधिकारी प्रभुदय मुळे मुख्याधिकारी शैलेश फडसे सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता तोंडे बीड़ पाटबंधारे विभाग के कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र पवार एमआईडीसी क्षेत्र व्यवस्थापक अतुल पाथरे अन्य संबंधित अभियंता और अधिकारी यह बैठक बीड़ जिले के समग्र विकास को गति देने और स्व. अजितदादा पवार के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

लोकों को ब्रह्मज्ञान सिखाने वाले खुद ...

इसकी आलोचना की है। इसका मतलब है कि देश की स्थिति खतरनाक होती जा रही है।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत असुरक्षित होता जा रहा है। सामान्य जनता के सामने अनाज और रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने की आशंका है। देश पर संकट आने पर कांग्रेस ने हमेशा सर्वपक्षीय भूमिका अपनाई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी विदेश दौरे पर प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री सर्वपक्षीय बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं। इसलिए शरद पवार का दिया गया सुझाव सही है।

अशोक खरात प्रकरण को दबाने का प्रयास

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे पर दया आती है, ऐसा कहते हुए पटोले ने बताया कि उनके अपने मुख्यमंत्री ने इस मामले को महिलाओं से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा बताया था। इस मामले में कई महिलाओं के शोषण का आरोप है।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद इस प्रकरण में शामिल चार मंत्रियों के खिलाफ सबूत पेश किए जाएंगे। सरकार द्वारा गठित डखढ की सीमाएं तय कर दी गई हैं और पीड़ित महिलाओं से जानकारी ली जा रही है। लेकिन बाद में इस मामले को एऊको सौंप दिया गया। राज्य में एजथ जैसी एजेंसी होने के बावजूद एऊ को जांच सौंपने की क्या जरूरत पड़ी? क्या राज्य सरकार को अपने ही पुलिस पर भरोसा नहीं है? - यह सवाल उठ खड़ा हुआ है।

इस मामले में बड़े पैमाने पर आर्थिक लेन-देन का आरोप है। इसलिए इसे दबाने का प्रयास हो रहा है या नहीं, ऐसी शंका पैदा हुई है। दोषी मंत्रियों और अधिकारियों को हटाने के बजाय उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री समय बर्बाद कर रहे हैं, ऐसी भावना जनता में है। हम इसे आरोप नहीं, हकीकत मानते हैं।

राज्य में धर्म के नाम पर भोंदूगिरी (धांधली) तेजी से बढ़ रही है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई किए बिना महाराष्ट्र को लगी यह बीमारी नहीं रुकेगी।

नाशिक के डडघ होटल की घटना और खरात प्रकरण के बीच आपसी संबंध होने का संदेह है। यह पूरी साखली (श्रृंखला) है। अगर सरकार समय रहते गंभीरता से कार्रवाई करती तो कई महिलाओं को बचाया जा सकता था। इसलिए इस घटना के लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है।

नीट पेपर लीक प्रकरण में ...

ही नहीं, बल्कि २२.६९ लाख परिवारों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में यह दूसरी बार नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। वर्ष २०२४ में छएएढ-णऋपेपर लीक हुआ था। शुरुआत में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक के आरोपों को खारिज किया था, लेकिन बाद में बिहार और हजारीबाग में गड़बड़ी स्वीकार की थी और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। लेकिन अब फिर पेपर लीक होने से साफ है कि कोई सुधार नहीं हुआ।

महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस के शासनकाल में पेपर लीक के कई मामले सामने आए, लेकिन उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा मुख्यमंत्री फडणवीस ने उद्दंड बयान दिया था कि गलत खबर देने वालों पर कार्रवाई करेंगे।

२ मई २०२६ को दौंड में डठझऋसिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में १०० में से ८५ सवाल एक निजी प्रकाशक की किताब से ज्यों के त्यों पूछे गए थे। यह भी स्पर्धात्मक परीक्षा में बड़ा गड़बड़झाला है।

सपकाळ ने कहा कि भाजपा सरकार को परीक्षाएं भी ठीक से नहीं आयोजित हो रही हैं, यह उनकी अक्षमता का स्पष्ट संकेत है।

महाराष्ट्र के लिए अगले तीन...

अकोला और नंदुरबार जिलों का तापमान ४५.३ डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। वर्तमान में राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान ४० डिग्री से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने नागरिकों को अगले तीन दिनों तक विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले पांच दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है, जिसके कारण तापमान में कमी आने की उम्मीद बहुत कम है। वहीं भारतीय मौसम विभाग (खचऊ) ने विदर्भ क्षेत्र में अगले चार से पांच दिनों के दौरान तापमान में भारी वृद्धि होने की चेतावनी दी है। विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है।

गौरतलब है कि अप्रैल महीने में इस सीजन का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया था। उसके बाद कुछ दिनों तक मौसम में हल्की राहत मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर तापमान तेजी से बढ़ने लगा है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।

नागपुर, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, यवतमाल और वर्धा जिलों में गर्मी की तीव्रता लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय अत्यावश्यक काम के अलावा घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है।

मोदी पहले अपने दौरे और काफिले ...

इस खर्च और ईंधन की खपत का हिसाब कौन देगा?

उन्होंने आगे कहा कि कच्चे तेल की कीमतें ९०-१०० डॉलर प्रति बैरल तक जाना कोई नई बात नहीं है। २००८, २०११-१२, २०१३-१४ और २०२२-२३ में भी ऐसी स्थिति आई थी।

जब कच्चा तेल ६०-६५ डॉलर प्रति बैरल था, तब भी जनता को महंगा पेट्रोल-डीजल बेचा गया। सरकार ने उससे लाखों करोड़ रुपये कमाए। वो पैसा आखिर गया कहाँ?

राज ठाकरे ने कहा कि देश और राज्यों की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, लेकिन सरकार सारा दोष केवल ईरान-इजरायल युद्ध पर डाल रही है। उन्होंने भाजपा की चुनावी रैलियों और रोड शो पर भी सवाल उठाए।

जनता को विदेश दौरे टालने की सलाह देने वाले प्रधानमंत्री खुद १५ मई से ५ देशों के दौरे पर जाने वाले हैं। पहले ये दौरे रद्द करें, फिर जनता से अपील करें।

उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण देते हुए कहा कि शास्त्रीजी ने युद्ध के समय जो अपील की, उसे खुद अमल में उतारा था। आज का नेतृत्व वैसा कर पाएगा क्या?

शरद पवार की मांग:

शरद पवार ने कहा कि सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और ईंधन दरों के मुद्दे पर जनता के सामने सच्चाई रखनी चाहिए। सिर्फ जनता को संयम बरतने की अपील करने से काम नहीं चलेगा।

उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री अपनी अध्यक्षता में तुरंत सर्वपक्षीय बैठक बुलाएं, सभी दलों के नेताओं को विश्वास में लेकर फैसले लें। साथ ही देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों की बैठक बुलाकर स्थिति का गहन विश्लेषण किया जाए।

कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया:

नाना पटोले, हर्षवर्धन सपकाळ और सचिन सावंत ने भी कहा कि जनता को किफायत सिखाने से पहले सत्ताधारी दल को अपने खर्च - जाहिरात, रोड शो, सुरक्षा काफिले और विदेश दौरे - कम करने चाहिए। अगर स्थिति गंभीर है तो संसद में चर्चा होनी चाहिए और सरकार को स्पष्ट रोडमैप पेश करना चाहिए।

शिक्षण अधिकारियों की मनमानी पर...

न्यायमूर्ति विभा कंकणवाडी और न्यायमूर्ति अजित बी. कडेठाणकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग के रवैये पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।

- न्यायालय बार-बार स्पष्ट आदेश दे रहा है, इसके बावजूद शिक्षा अधिकारी जानबूझकर आदेशों की अनदेखी कर गलत निर्णय ले रहे हैं।

- अदालत में बुलाए जाने के बाद अधिकारी बिना शर्त माफी मांग लेते हैं, लेकिन बाद में फिर वही गलती दोहराते हैं। इस बार अदालत ने केवल चेतावनी देकर छोड़ा है, लेकिन भविष्य में सीधे कार्रवाई की जाएगी।

- सर्वोच्च न्यायालय ने अंजुमन इसाअत-ए-तालीम ट्रस्ट मामले को बड़ी पीठ के समक्ष विचारार्थ भेजा हुआ है, इसलिए तब तक शिक्षा अधिकारी टीईटी अनिवार्यता का आग्रह नहीं कर सकते।

- १७ अक्टूबर २०२५ के सरकारी परिपत्र के अनुसार अल्पसंख्यक स्कूलों पर आरटीई (ठढए) लागू नहीं होता, इसलिए वहां टीईटी की शर्त भी लागू नहीं होती।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रखने वाले वकील

इस महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से निम्नलिखित वकीलों ने पैरवी की:

- ॲड. सैयद तौसिफ यासीन - सय्यद अबू ज़ैद व अन्य की ओर से

- ॲड. शेख तारेक मोबिन एच. - गायकवाड सायली व्यंकटेश की ओर से

- ॲड. के. पी. रोडगे - साईनाथ गणपत बनसोडे की ओर से

खंडपीठ का अंतिम आदेश

न्यायालय ने शिक्षा अधिकारियों के पुराने आदेश रद्द कर दिए हैं तथा संबंधित संस्थाओं को १५ दिनों के भीतर नए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट आदेश दिया कि प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद किसी भी परिस्थिति में टीईटी पात्रता की शर्त न लगाई जाए और एक महीने के भीतर नियुक्तियों को मंजूरी दी जाए।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com